

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 29 नवम्बर, 2011

विषय:- जनपद चम्पावत की तहसील पूर्णागिरी (टनकपुर) के अंतर्गत राजस्व विभाग की स्वामित्व की लीसा डीपो वाली 0.806 हैं भूमि को राजकीय महाविद्यालय, टनकपुर को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2560/पच्चीस-02/(2008-09) दि-016.7.2011 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, जनपद चम्पावत की तहसील पूर्णागिरी (टनकपुर) के अंतर्गत खाता खतौनी सं-209 खसरा सं-319 मध्ये राजस्व विभाग की स्वामित्व की लीसा डीपो वाली 0.806 हैं भूमि को राजकीय महाविद्यालय, टनकपुर को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में वन विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति एवं वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15-02-02 के प्राविधानों के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1— भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2— जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
- 3— हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4— यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- 5— जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6— जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7— प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्यों के लिए नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृष्ठां संख्या—२३७। / समिति/ २०११

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4— आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- 5— निदेशक, एनोआईसी० सचिवालय।
- 6— प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।
- 7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।